दिल्ली में राजनीतिक दलों के सदस्यों को सुरक्षा

1718. **मोहम्मद अफजल उर्फ, भीम अफजल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 1992 से 30 अगस्त, 1993 तक दिल्ली में राजनीतिक दलों के कितने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की गई थी;

(ख) इन राजनीतिक दलों के नाम क्या हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कौन-कौन से राजनीतिक दलों के कितने सदस्यों की सुरक्षा वापस ली गई; और

(घ) सुरक्षा वापस लेने के क्या कारण थे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) और (ख) दिल्ली में 1.1.92 से 30.8.93 तक निम्नलिखित राजनीतिक दलों के 93 सदस्यों को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान की गयी थी:—

(i) कांग्रेस (आई)
(ii) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)
(iii) जनता दल
(iv) शिव सेना
(v) जनता पार्टी
(vi) झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)
(vii) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
(viii) नेशनल पीपुल्स कान्फ्रेंस।
(ix) बजरंग दल
(x) कांग्रेस (एस०)
(xi) तेलगू देशम पार्टी

(ग) 1.1.92 से 30.8.93 तक की अवधि के दौरान निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों के 33 सदस्यों को दी गयी सुरक्षा वापस ली गयी:—

(क) कांग्रेस (आई)	16
(ख) जनता दल	5
(ग) तेलगू देशम पार्टी	6
(घ) जनता दल (अ०)	1
(ङ) भारतीय जनता पार्टी	3
(च) समाजवादी जनता पार्टी	1
(छ) जन मोर्चा	1

(घ) सुरक्षा की आवश्यकता का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में संशोधन किया जाता है। वापस ली जाती है, जैसी भी परिस्थितियां हों।

1719. [Transferred to 23rd December, 1993]

Insurgency in North Eastern States

1720. DR. MURLI MANOHAR JOSHI: SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to State:

(a) what are the details of persons killed by insurgents and armed terrorists and rebels in each of the States in North-Eastern region during the last six months; and

(b) what steps have been taken by Government in each of the above States to curb the menace of insurgency?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) The state-wise figures as available are as follows:

1.	Arunchal Pradesh	... 05
2.	Assam	... 47
3.	Manipur	... 415
4.	Meghalaya	... 02
5.	Mizoram	... 02
6.	Nagaland	... 45
7.	Tripura	... 29

(b) The measures taken include declaring some of the militant organisations as Unlawful Associations under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967; counter-insurgency operations by the Security Forces; and, encouragement to the activists of these organisations to join the mainstream of the national life provided they eschew violence and abide by the Constitution of India. Besides, the whole of Assam and Manipur, a 20 km. belt from Assam border into the neighbouring States of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland, Tirap and Changlang districts of Arunachal Pradesh and Mon district of Nagaland continue to be